POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में राजस्थान सहित कई राज्यों में लंपी वायरस नामक बीमारी मवेशियों में खासतौर पर गोवंश पर कहर ढा रही है। मानसून की शुरुआत से ही इस बीमारी का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में ही जहां हजारों की संख्या में मवेशी इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं वहीं बड़ी संख्या में हो रही गायों की मौत ने लोगों के दिलों को दहला दिया है।

राहत से भरी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बड़े स्तर पर इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में लगी है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। देश के कई राज्यों में इस बीमारी से पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ है।

पशुधन पर यह खतरा जहां पशुपालकों और किसानों की आय को प्रभावित करता है वहीं दुग्ध उत्पादन और इसकी गुणवत्ता पर भी बुरा असर ड़ालता है।

मोदीजी ने आश्वस्त किया है कि सरकार पशुधन के सार्वभौमिक टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम 2025 तक पशुओं के 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि भारत डेयरी पशुओं का डेटाबेस बना रहा है और इसमें डेयरी से जुड़े हर जानवर को टैग किया जा रहा है। जानवरों की बायोमेट्रिक पहचान भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का नाम पशु आधार रखा गया है।

इस समय अहम जरूरत यह है कि संक्रमण से बचाव के उपाय किए जाए तथा मवेशियों के टीकाकरण के लिए शहरों और गांवों में बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाएं। पशुपालकों और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के साथ ही दुग्ध उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए।

'कट्स' की याचिका पर एनजीटी का फैसला

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को वाहनों के हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने व नियमों की पालना करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि वाहन निर्माता को बिक्री के स्थान और तकनीकी प्रचार सामग्री में वाहनों के ध्वनि स्तर के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें ध्वनि के स्तर को अपनी बेवसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा। जनता चैन से सो सके, इसके लिए एनजीटी ने प्रदेश में आवासीय क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नो हॉन्किग जोन रखने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके अतिरिक्त अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों को 5,000 रुपए से दंडित कर उक्त राशि एक कोष में डाली जाने व उस अपराध की पुनरावृत्ति पर अपराधी से 10,000 रुपए की राशि दण्ड स्वरूप वसूलने और हॉर्न बजाने के उपकरण को जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 'कट्स' की याचिका पर फैसला देते हुए एनजीटी ने 'कट्स' को इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन के साथ वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटीज व समाजिक संगठनों को शामिल करने को कहा है।

एनजीटी भोपाल की बेंच में 'कट्स' के अधिवक्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में शांतिपूर्वक जीने का अधिकार शामिल है। किसी भी तरह की तेज आवाज जिससे व्यक्ति की शांति व आराम में बाधा पहुंचे, यह अधिकारों का हनन है। याचिका में ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के पूर्व फैसलों की पालना करवाने की गुहार की।

सांप काटने से आया था अटैक; बीमा कंपनी क्लेम दें

दौसा जिले के नांगल राजावतान निवासी मुकेश मीना ने राज्य उपभोक्ता आयोग में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जिला उपभोक्ता आयोग दौसा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दर्ज कराई। मीना ने राज्य आयोग को बताया कि पिता लल्लूराम ने 17 जून 2014 को 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया था। सांप के काटने से उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने क्लेम का दावा किया, लेकिन कंपनी ने डेथ अटैक से कहकर क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी बीमा कंपनी को सही माना, जबकि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुए अटैक के कारण हुई थी।

मामले की सुनवाई पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने सांप के काटने से आए अटैक के चलते हुई बीमित व्यक्ति की मौत को नेचुरल मृत्यु की बजाय एक्सीडेंटल मृत्यु माना। आयोग ने कहा बीमित व्यक्ति लल्लूराम को सांप के काटने से अटैक आया था। राज्य आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिजनों को 10 लाख रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित दे। इसके अलावा 20 हजार रुपए मानसिक परेशानी व परिवाद खर्च के भी दिए जाएं।

'भारत' ब्रांड के तहत बिकेंगे उर्वरक

उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू की है। इससे आगामी रबी सीजन में किसानों को एक जैसी खाद मिलेगी। यह कंपनियों के बजाय भारत ब्रांड नाम से जानी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके 'भारत' ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे।

केंद्र ने यह निर्देश सभी उर्वरक कारखानों, ट्रेडिंग और मार्केटिंग कंपनियों को दिया है। खाद की बोरी पर एक साइड़ के दो तिहाई हिस्से पर नए ब्रांड और लोगों का उल्लेख होगा। बाकी एक तिहाई में कंपनी अपना ब्योरा और निर्धारित तथ्य प्रिंट करेगी। हर बोरी पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना छपा रहेगा। खाद की बोरियों पर दर्ज प्रतीक चिन्ह (लोगो) से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उर्वरक केंद्रीय सब्सिडी वाली है।

प्रदेश में जारी हुई नई हस्तशिल्प नीति

राजस्थान में पंजीकृत छह लाख हस्तशिल्पियों के लिए करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद नई हस्तशिल्प नीति जारी कर दी गई है। केबिनेट से मंजूर प्रदेश की इस पहली नीति में हस्तशिल्पियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। हस्तशिल्पियों को तीन लाख रुपए तक के ऋण पर देय ब्याज अब सरकार वहन करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हस्तशिल्पियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान भी नीति में शामिल है। इसके अलावा हस्तशिल्पियों को समूह बीमा मुहैया कराने, हर साल राज्यस्तरीय पुरस्कार देने, हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने, मार्केटिंग की व्यवस्था करने जैसे कई प्रावधान इस नीति में शामिल किए गए हैं।

भारत कृषि क्षेत्र में वैश्विक अगुआ बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना होगा। इस तरह भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही कृषि क्षेत्र में वैश्विक रूप से अगुआ बन सकता है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन यापन में सुगमता लाने, सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी बनाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो देश मे तेजी से हो रहा शहरीकरण कमजोरी की बजाय एक ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री ने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से करने की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा के अनुसार महिला समानता दिवस पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए महिला निधि योजना का लोकार्पण किया।

इस योजना के तहत 40 हजार रुपए तक के ऋण 48 घंटे में व 40 हजार रुपए से अधिक के ऋण 15 दिवस में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1.42 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में स्वीकृत की।

नई पहलः किसानों की बढ़ेगी आय

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) अब दूध के साथ गाय-भैंस का गोबर भी खरीदेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 9.50 करोड़ रुपए की लागत से एनडीडीबी मृदा लिमिटेड़ नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है, जो नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहयोगी कंपनी होगी।

यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कंपनी की शुरुआत करते हुए दी है। इस नई पहल के तहत कंपनी गाय-भैंस के गोबर से बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाएगी। उन्होंने बताया कि जैविक खाद को एक सामान्य पहचान प्रदान करने के लिए सुधन नाम से ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया है। इस प्रोडक्ट का करोबार 'सुधन' के नाम से किया जाएगा।

लंपी वायरस का स्वदेशी टीका तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग (लंपी स्किन डिजीज) के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसकी रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा हम 2025 तक पशुओं के 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई राज्य मवेशियों में फैले इस रोग से जूझ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में लंपी वायरस नाम की इस बीमारी से पशुधन का नुकसान हुआ है। यह किसानों की आय को प्रभावित करता है।

जैविक उत्पादों को मिला ग्लोबल बाजार

भारतीय जैविक उत्पादों को ग्लोबल बाजार मिलने लगे हैं। इससे देश का जैविक उत्पादों का निर्यात भी बढ़ रहा है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच भारत ने अमरीका-यूरोप सहित कई देशों को 1.98 करोड़ टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया, किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

निर्यात में 50 फीसदी से भी अधिक उत्पाद अमरीका और 37 फीसदी उत्पात यूरोपियन यूनियन के देशों को निर्यात किया गया। विदेशों में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है और उम्मीद है वर्ष 2025 तक इसका वैश्विक बाजार 150 अरब डॉलर हो जाएगा।

निरक्षरों के लिए होगी डिजिटल कक्षा

निरक्षरों की पढ़ाई अब आधुनक तरीके से होगी। अब उनके हाथों में स्लेट-पैंसिल नहीं होगी बल्कि डिजिटल कक्षा लगेगी। अध्ययन सामग्री भी मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा भी ऑन लाइन होगी।

इसके लिए पहली बार 11 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राज्य में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बार पांच लाख निरक्षरों को साक्षर बनाया जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 48 हजार स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं।

पीएम श्री योजनाः बनेंगे मॉडल स्कूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर में 14 हजार 500 स्कूलों को विकसित व क्रमोन्नत करके पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) स्कूल में तब्दील करने की घोषणा की है। यह मॉडल स्कूल देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे। देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी एवं समग्र अनुसंधान आधारित तरीके से होगी। यह स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। स्कूलों को विकसित करने का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। राज्य सरकारों से सरकारी स्कूलों को इनमें तब्दील करने के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे।

पेड़ों को काटे बगैर बन सकते हैं समृद्ध

कर्नाटक के होन्नाली के घने जंगल में करीब 80 साल की बुजुर्ग महिला पद्मश्री तुलसी गौड़ा बिना पढ़ाई-लिखाई के पेड़ों के बारे में दुलर्भ जानकारियां रखती है। जब वह किसी को पेड़ों और बीजों के बारे में बताती है तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तुलसी ने अपनी पूरी जिंदगी कर्नाटक में बंजर जमीन को जंगलों में बदलने में समर्पित कर दी।

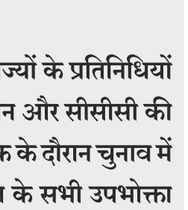

तुलसी कहती है पेडों को काटे बगैर इंसान समृद्ध बन सकते हैं। जब वह पेड़ों का महत्व बताती है तो गांव के लोग आदर से सिर झुका लेते हैं। पद्मश्री सम्मान लेने के लिए वह पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में बिना पैरों में कुछ पहने पहुंची थीं। पूरी जिन्दगी में कभी जूते नहीं पहने। छात्रों से भरी बसें उनके घर पेड़ों के बारे में जानकारी लेने पहुंचती तो उनकी बांछे खिल उठती है।

'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन चुने गए कन्ज्यूमर कोआर्डिनेशन कौंसिल के उपाध्यक्ष

जयपुर स्थित 'कट्स' इंटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन 9 सितंबर 2022 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के दौरान भारत की कन्ज्यूमर कोआर्डिनेशन कौंसिल (सीसीसी) के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। सीसीसी के संविधान के अनुसार, चुनाव दो साल में एक बार होता है और उपाध्यक्ष बनने के दो साल बाद स्वतः सीसीसी का अध्यक्ष बन जाता है।

भारत के 22 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सम्मेलन और सीसीसी की वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान चुनाव में भाग लिया। सीसीसी भारत के सभी उपभोक्ता संगठनों का सर्वोच्च उपभोक्ता निकाय है और भारत के उपभोक्ताओं की आवाज है, जिसकी स्थापना 1983 में भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए की गई थी।

किसानों के लिए एफपीओ बन रहे हैं वरदान

'कट्स' द्वारा नाबार्ड के सहयोग से आदिवासी जिले बांसवाड़ा के तलवाड़ा में चमकीला हींश किसान प्रॉड्यूसर कंपनी के नाम से एक कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया गया है। इसका उद्घाटन नाबार्ड के सीजेएम बी.एन. कुरप ने जून माह में किया। एफपीओ ने किसानों को वाजिब दाम पर अच्छी क्वालिटी के बीज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।

इस एफपीओ ने सितम्बर माह तक पांच लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर साबित कर दिया है कि किसानों के लिए एफपीओ किसी वरदान से कम नहीं है। क्षेत्र के किसानों में भी खुशी का माहौल है। उन्हें अब खाद बीज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। (अधिक जानकारी के लिए 'कट्स' मानव विकास केंद्र, बांसवाड़ा से संपर्क कर सकते हैं)

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर